बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 115 ● नई दिल्ली ● शनिवार 14 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

बांग्लादेश में जिहादी हिंसा के शिकार हो रहे हिंदू, तारिक रहमान सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की उम्मीद

नई दिल्ली। बांग्लादेश में प्रचंड बहुमत से बीएनपी की सरकार आ रही है। खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विहिप ने उम्मीद जताई है कि उनके कार्यकाल में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले रुकेंगे। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि पिछले दिसंबर में बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से ही वहां हिंदुओं पर लगातार होते प्राण घातक हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को कमालगंज उप जिला अंतर्गत इस्लामपुर के मौलवी बाजार इलाके में स्थित चंपारा चाय बागान में काम करने वाले 28 वर्षीय हिंदू रतन शुभोकर का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला।

दिल्ली एमसीडी बजट सदन में पेश, सफाई कर्मियों और शिक्षा पर जोर

नई दिल्ली।

दिल्ली में आज शुक्रवार को एमसीडी सदन में बजट रखने की प्रक्रिया हर-हर महादेव, भारत माता की जय और वन्दे मातरम् जैसे नारों के साथ शुरू हुई। हालांकि, इन नारों पर विपक्ष ने एतराज जताया है। बता दें कि यह बजट नेता सदन प्रवेश वाही द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। प्रवेश वाही सामने की तीसरी सीट से बजट पढ़ने जा रहे थे, इस पर भी विपक्ष को आपत्ति हुई। प्रवेश वाही ने बताया कि 5000 सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। ये वर्ष 2000 से 2002 के बीच नियुक्त हुए हैं। बजट में जनता की सुविधाओं के लिए शौचालय स्वच्छ रहे, इसलिए शौचालयों, ड्रेन एवं कल्वर्ट के रख-रखाव के लिए प्रत्येक वार्ड में अलग से पांच लाख रुपये का प्रविधान किया है। इसके लिए बजट में कुल 2.5 करोड़ रुपये बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड दिया है, जिसे जनता की सुविधा के लिए निगम द्वारा पूरी दिल्ली में स्वच्छता कार्यों के लिए जल्द से जल्द उपयोग किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने 14 मैकेनिकल रोड, स्वीपिंग मशीनें खरीदने का ऑर्डर कर दिया है। इसके अतिरिक्त 17 बैकहो लोडर, दो सुपर सकर मशीन, 10 स्किड स्टीयर लोडर एवं अन्य मशीनें खरीदी गई हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें जल्द ही बेड़े में शामिल कर दी जाएंगी। प्रत्येक

विधानसभा में एक-एक मशीन दी जाएगी, जिससे सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसी प्रकार 1000 लिटर पिकर मशीनें जल्द ही आ रही हैं और प्रति वार्ड में 4-4 लिटर पिकर दिए जाएंगे, जिससे कोने-कोने व मुश्किल जगहों से हर महीने कूड़ा भी साफ हो सकेगा। 318 से अधिक बाजारों में रात्रिकालीन व्यवस्था की शुरुआत की है। करीब 550 किमी रोड रात्रि में ही साफ किए जा रहे हैं। डीडीए से हस्तांतरित मार्केट्स के लिए प्रत्येक वार्ड में 100 अतिरिक्त सफाईकर्मी दिए जाएंगे। इससे क्षेत्र का चेहरा बदलेगा। यह पहली बार भाजपा के शासनकाल में किया गया है। इससे वहां गंदगी पर भी अंकुश लगेगा।

प्रवेश वाही ने कहा, यह कहते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा निगम स्वच्छता पायदान में 90वें स्थान से 31वें स्थान पर आया है। आने वाले समय में इसमें हम प्रथम 10 शहरों में अवश्य स्थान प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में बच्चों को दी जाने वाली प्राथमिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1514 प्राथमिक विद्यालय, 43 अनुदान प्राप्त विद्यालयों एवं 862 मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा लगभग छह लाख 59 हजार बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रवेश वाही ने बताया कि सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों का वितरण, नोट बुक, स्टेशनरी, स्कूल बैग, मुफ्त वर्दी, जर्सी, जूते के बदले नकद धनराशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। मुफ्त मिड-डे-मील की व्यवस्था एवं विभिन्न प्रकार की छात्रवृति प्रदान की जा रही है। निगम विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के दुर्घटना बीमा राशि अभी तक 50 हजार रुपये थी, जिसे इस वर्ष बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी है। दिल्ली नगर निगम के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सभी छात्रों को दी जाने वाली वर्दी, स्टेशनरी और स्कूल बैग आदि का पैसा लगभग 71.11 करोड़ रुपये वन क्लिक के माध्यम से उनके खाते में ट्रांस्फर किए गए हैं।

दिल्ली मेट्रो फेज-V(A) से बदलेगी राजधानी की रफ्तार, 12 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को नई गति देने की तैयारी तेज हो गई है. मेट्रो फेज-V(A) को मिली कैबिनेट मंजूरी के साथ शहर के ट्रैफिक, प्रदूषण और यात्रा समय को लेकर एक बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है. यह परियोजना केवल नई लाइनें नहीं, बल्कि दिल्ली की भविष्य की आवाजाही की दिशा भी तय करेगी. दिल्ली मेट्रो फेज-V(A) के तहत कुल 12,014.91 करोड़ रुपये की लागत से तीन नए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे. इस परियोजना में दिल्ली सरकार का हिस्सा 2,940.46 करोड़ रुपये तय किया गया है. सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2028 तक इन सभी कॉरिडोर को आम जनता के लिए चालू कर दिया जाए.

16 किलोमीटर के नए नेटवर्क में 13 स्टेशन होंगे शामिल

फेज-V(A) में लगभग 16 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो नेटवर्क जोड़ा जाएगा. इस विस्तार में कुल 13 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें 10 अंडरग्राउंड और 3 एलिवेटेड स्टेशन होंगे. यह नए स्टेशन मौजूदा नेटवर्क से सीधे जुड़े रहेंगे, जिससे यात्रियों को निर्बाध इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी.

तीन नए कॉरिडोर से मुख्य इलाकों को सीधी कनेक्टिविटी

इस चरण में तीन प्रमुख कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है. पहला आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक का

कॉरिडोर होगा, दूसरा एयरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक और तीसरा तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक विकसित किया जाएगा. ये तीनों रूट प्रशासनिक, व्यावसायिक, आवासीय और एयरपोर्ट क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगे.

सेंट्रल विस्टा को मिलेगा सीधा लाभ

सबसे लंबा और महत्वपूर्ण कॉरिडोर आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक प्रस्तावित है. इसकी लंबाई करीब 9.9 किलोमीटर होगी और इसमें 9 स्टेशन बनाए जाएंगे. यह लाइन सेंट्रल विस्टा क्षेत्र से होकर गुजरेगी और कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल, भारत मंडपम जैसे अहम स्थानों को मेट्रो से जोड़ेगी. इससे रोजाना करीब 60 हजार कर्मचारी और लगभग 2 लाख यात्री लाभान्वित होने की उम्मीद है.

एयरपोर्ट यात्रा होगी और आसान

एयरोसिटी से घरेलू हवाई अड्डा टर्मिनल-1 तक प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई लगभग 2.26 किलोमीटर होगी. इस रूट पर एक स्टेशन बनाया जाएगा. मेट्रो की सीधी पहुंच से एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों की टैक्सी और निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी और एयरपोर्ट क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम होगा.

दक्षिण दिल्ली को मिलेगी राहत

तीसरा कॉरिडोर तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक 3.9 किलोमीटर लंबा होगा. इस रूट पर 3 स्टेशन प्रस्तावित हैं. इससे दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और स्थानीय यात्रियों का समय बचेगा.

ट्रैफिक, प्रदूषण और ट्रैवल टाइम में कमी का दावा

सरकार के मुताबिक इस मेट्रो विस्तार से सड़कों पर वाहनों का दबाव घटेगा. निजी गाड़ियों के कम इस्तेमाल से प्रदूषण में कमी आएगी और औसत यात्रा समय भी घटेगा. मेट्रो को नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

यह दिल्ली के भविष्य में निवेश- सीएम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को राजधानी के भविष्य में किया गया निवेश बताया है. उनका कहना है कि मेट्रो नेटवर्क का विस्तार दिल्ली को विश्वस्तरीय और पर्यावरण-अनुकूल शहर बनाने में मदद करेगा. सरकार केंद्र के साथ मिलकर एकीकृत और जन-केंद्रित परिवहन व्यवस्था विकसित करने पर काम कर रही है.

सुविधा बढ़ने के साथ किराया बना चिंता का कारण

मेट्रो विस्तार को लेकर यात्रियों की राय मिली-जुली सामने आ रही है. यात्री प्रवीण का कहना है कि मेट्रो से समय और ट्रैफिक की परेशानी तो कम हुई है, लेकिन बढ़ता किराया खासकर छात्रों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है. उन्होंने छात्रों के लिए रियायती मेट्रो पास की मांग की है.

यात्रियों का क्या कहना है?

यात्री शुभम पांडेय का कहना है कि नई लाइनों में तकनीक तो आधुनिक है, लेकिन कुछ सुविधाएं पुरानी लाइनों जैसी जमीनी स्तर पर महसूस नहीं होतीं. उनके अनुसार मेट्रो का सबसे बड़ा फायदा ट्रैफिक से बचाव और समय की बचत है, लेकिन किराए का असर आम लोगों की जेब पर साफ दिख रहा है.

दिल्ली के स्कूलों में मिली बम की धमकी, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली ।

राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों में आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें तुरंत हरकत में आ गईं। विभिन्न स्कूलों में बम निरोधक दस्ते और पुलिस के जवान पहुंच गए हैं और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, बम की धमकी का पहले झंडेवालान स्थित बीडी तमिल एजुकेशन स्कूल को मिली। इसके बाद अन्य स्कूलों से भी इसी तरह की धमकियों की खबरें सामने आने लगीं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी संवेदनशील स्कूलों को अलर्ट कर दिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। फिलहाल, दिल्ली पुलिस की टीमें और बम निरोधक दस्ता स्कूलों के अंदर और आसपास के इलाकों में किसी भी संदिग्ध वस्तु की तलाश में जुटा हुआ है। बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, कई स्कूलों को एहतियात के तौर पर खाली कराया गया है। छात्रों और शिक्षकों को शांत रहने और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और धमकी भरे कॉल के स्रोत का पता लगाने का प्रयास कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या यह किसी संगठित गिरोह का काम है या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा फैलाई गई अफवाह।

पूर्व पीएम नेहरू ने सुप्रीम कोर्ट जज से मांगी थी माफी, जयराम रमेश बोले- ऐसे थे असाधारण संस्थान निर्माता

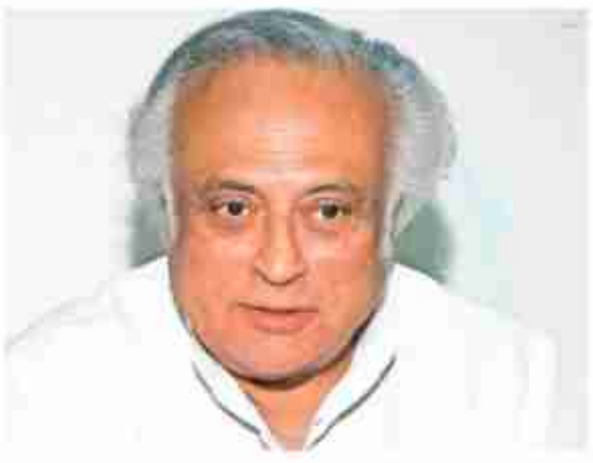

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ की। उन्होंने नेहरू को असाधारण संस्थान निर्माता बताया। रमेश ने याद दिलाया कि कैसे साल 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने सुप्रीम कोर्ट के जज विवियन बोस को एक माफीनामा लिखा था। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पत्र को साझा किया। उन्होंने लिखा कि आजकल सरकार और न्यायपालिका के बीच के रिश्तों पर बहुत बातें होती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नेहरू का 26 जून 1959 को जस्टिस विवियन बोस को लिखा गया यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। रमेश के अनुसार, यह पत्र दिखाता है कि नेहरू संस्थाओं का कितना सम्मान करते थे जस्टिस बोस को लिखे अपने पत्र में पीएम नेहरू ने अपनी गलती स्वीकार की थी। उन्होंने लिखा था कि वे पिछले कई दिनों से लगातार यात्रा कर रहे हैं। उनका इरादा था कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई कुछ बातों के बारे में पहले ही पत्र लिखें, लेकिन व्यस्तता के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। नेहरू ने कहा था, कुछ दिन पहले जब मैं त्रिवेंद्रम में था, तो मुझे कलकत्ता बार लाइब्रेरी क्लब के ऑनरेरी सचिव का एक लेटर मिला, जिसके साथ उन्होंने कलकत्ता बार की एक मीटिंग में पास किया गया एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें मैंने आपके बारे में जो कुछ कहा था, जिसे गलत बताया गया था। जैसे ही मुझे यह लेटर मिला, मैंने कलकत्ता बार लाइब्रेरी क्लब के सेक्रेटरी को जवाब भेज दिया। इसके बाद नेहरू ने जस्टिस बोस से निजी तौर पर माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही थीं, उन पर उन्हें बहुत दुख है। नेहरू ने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि उनकी वे बातें गलत थीं और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नेहरू ने अपनी सफाई में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवालों से वे काफी हैरान थे। उस समय उनके दिमाग में कई और बातें भी चल रही थीं, जिस वजह से उनसे गलती हुई। पत्र के अंत में नेहरू ने उम्मीद जताई कि जस्टिस बोस उनकी इस गलती को माफ कर देंगे।

ई-बस से जुड़ीं दिल्ली की अदालतें, डीटीसी ने शुरू की देवी सेवा; बड़े मेट्रो स्टेशनों से भी रहेगा कनेक्शन

नई दिल्ली । दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने राजधानी की अदालतों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए तीन नए ईवी बस रूट शुरू किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट, रोहिणी कोर्ट और साकेत कोर्ट को द्वारका कोर्ट से जोड़ने के लिए बसें 12 फरवरी से यह बस सेवा शुरू हुई। 'देवी' नाम से शुरू की गई यह 9 मीटर लंबी ई-बसें फिलहाल प्रयोग के आधार पर चलाई जा रही हैं, जिससे वकीलों, कोर्ट स्टाफ और आम लोगों को समय पर अदालत पहुंचने में सुविधा मिलेगी। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के अधिकारियों के मुताबिक, सेवा सफल रहने पर इन रूटों को स्थायी किया जा सकता है। फिलहाल ये बसें प्रयोग के आधार पर शुरू हो रही हैं। यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो रूटों को स्थायी किया जा सकता है। डीटीसी के अधिकारी ने बताया कि विभाग ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रूटों की जानकारी अपडेट करने और बस स्टॉपों पर नए बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं। रूट डी-1901 दिल्ली हाई कोर्ट से द्वारका कोर्ट तक है। यह 25.2 किलोमीटर लंबा है और लगभग 1 घंटा 40 मिनट में पूरा होगा। इस रूट के मुख्य स्टॉप बड़ौदा हाउस, पटेल चौक मेट्रो, केंद्रीय टर्मिनल, धौला कुआं मेट्रो, शास्त्री बाजार, पालम रेलवे फ्लाईओवर, द्वारका सेक्टर 1 और सेक्टर 6 हैं। रूट डी-3902 रोहिणी कोर्ट से द्वारका कोर्ट तक चलता है, जिसकी दूरी 20 किलोमीटर है और समय लगभग 1 घंटा 25 मिनट है। इस रूट के मुख्य स्टॉप में सरस्वती विहार, मंगलपुर स्कूल, पीरागढ़ी मेट्रो, सुंदर विहार, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर मेट्रो, उत्तम नगर टर्मिनल मेट्रो और द्वारका सेक्टर 1 शामिल हैं। रूट डी-7901 साकेत कोर्ट से द्वारका कोर्ट तक है, इसकी दूरी 25.7 किलोमीटर है और लगभग 1 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी होती है। इसके मुख्य स्टॉप पीटीएस, लाडो सराय क्रॉसिंग, अंधेरिया मोड़, वसंत कुंज सेक्टर ए, महिपालपुर, पालम एयरपोर्ट, प्रह्लादपुर, पालम रेलवे फ्लाईओवर और द्वारका सेक्टर 1 है।

सभी मुख्य मेट्रो स्टेशनों से जुड़ी होंगी

तीनों रूट सभी मुख्य मेट्रो स्टेशनों से जुड़ेंगे, जिससे यात्रा और आसान हो जाएगी। प्रत्येक रूट पर 2-2 बसें चलेंगी, जो द्वारका डिपो-2 से संचालित होंगी। डी-1901 के लिए द्वारका कोर्ट से सुबह 07:45, 08:15, 11:40, 1:25 और दिल्ली हाई कोर्ट से 09:30, 10:00, 1:25 शाम 5 बजे तक है। वहीं, डी-3902 के लिए द्वारका कोर्ट से 07:30, 08:00, 11:00, 12:40 और रोहिणी कोर्ट से 09:00, 09:30, 12:40 और शाम 5 बजे की टाइमिंग है। यही नहीं, डी-7901 के लिए द्वारका कोर्ट से 07:25, 07:55, 11:10, 12:55 और साकेत कोर्ट से 09:00, 09:30, 12:55 और शाम 5 बजे चलेगी।

खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा

संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान में नौ मिलियन से अधिक भारतीयों के निवास के साथ यह क्षेत्र रोजगार की तलाश में भारतीय प्रवासियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बना हुआ है। भारत विश्व स्तर पर प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, जिसका अधिकांश भाग जीसीसी से आता है। प्रारंभ में भारतीय प्रवासी मुख्य रूप से निर्माण, घरेलू सेवाओं और रखरखाव सहित नीले-कॉलर क्षेत्रों में कार्यरत थे। हालांकि, हाल के वर्षों में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, वित्त, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सफेद-कॉलर नौकरियों में भारतीयों की बढ़ती संख्या देखी जा रही है आर्थिक लाभों के बावजूद, जीसीसी देशों में प्रवासन का अनुभव चुनौतियों से भरा है। सभी छह देशों में राजशाही शासन प्रणाली है, जिसमें श्रम अधिकार सीमित हैं, जिसके कारण मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें आती रहती हैं, खासकर कम आय वाले प्रवासी श्रमिकों के बीच एक महत्वपूर्ण चिंता विवादास्पद कफाला (प्रायोजन) प्रणाली है, जिसके तहत एक स्थानीय नियोक्ता (कफील) प्रवासी के कानूनी और रोजगार संबंधी स्थिति पर व्यापक नियंत्रण रखता है जिससे अक्सर शोषण और दुर्व्यवहार होता है, क्योंकि श्रमिक अपने प्रायोजक की अनुमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते या देश नहीं छोड़ सकते। जीसीसी देशों ने अपने श्रम कानूनों में सुधार करना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ ने श्रमिक सुरक्षा बढ़ाने और महामारी के बाद के श्रम बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होने के लिए कफाला प्रणाली के कुछ पहलुओं को संशोधित या समाप्त कर दिया। भारत से विदेशों में नौकरी करने गए कई युवाओं की दर्दभरी दास्तानें सामने आती रही हैं। अनेक कहानियां सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं। दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियर अमन भोला अप्रैल 2023 में कुवैत बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर गए थे। शुरुआत में नौकरी का अवसर अच्छा दिखाया गया था लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग निकली। अमन को इंटरव्यू में सामान्य कार्य घंटे, सही ओवरटाइम भुगतान और सम्मानजनक कामकाजी माहौल का भरोसा दिया गया था। कंपनी में मजदूरों से रोज़ लगभग 16 घंटे तक काम कराया जाता था। कानून के अनुसार अधिकतम कार्य सीमा और 125 प्रतिशत ओवरटाइम भुगतान का प्रावधान है लेकिन अमन के अनुसार मजदूरों को केवल लगभग 65 प्रतिशत भुगतान मिलता था। इसी को लेकर मजदूरों की शिकायतें लगातार सामने आने लगीं। अमन ने बताया कि अधिकतर शिकायतें कंपनी की एचआर टीम के खिलाफ थीं। काम के घंटे, वेतन और सुविधाओं को लेकर बार-बार सवाल उठाने पर उन्हें दबाने की कोशिश की गई। जब अमन ने मजदूरों की समस्याएं प्रबंधन तक पहुंचाई तो उन्हें इंजीनियर से फोरमैन बना दिया गया। बाद में मैनेजर और कंपनी मालिक से अनुरोध के बाद उन्हें फिर से इंजीनियर पद पर बहाल किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आवाज़ उठाने वालों पर दबाव बनाने के लिए पद और पोस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अमन ने कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर में श्रम कानून उल्लंघन का मामला दर्ज कराया तो उनके साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हुआ और मारपीट की गई। वह एक वर्ष तक बिना नौकरी के न्याय के लिए लड़ते रहे। बाद में उन पर पुलिस में झूठा मामला दर्ज कराकर भारत निर्वासित कर दिया गया।

ऐसी ही कहानी विश्वकर्मा की भी है। उसने अच्छी नौकरी के नाम पर एजेंट को भारी रकम दी और अपनी दुकान तक बेच दी लेकिन विदेश पहुंचने के बाद उनसे जबरन निर्माण कार्य कराया गया। उत्तराखंड के विशाल , रंजीत , लल्लन और जुगेश को पानी की बोतलों की पैकिंग का काम बताया गया था लेकिन दुबई पहुंचकर उनसे भीषण गर्मी में भारी मजदूरी कराई गई। बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर मदद मांगी। उत्तर प्रदेश के मोहम्मद ड्राइवर की नौकरी के नाम पर सऊदी अरब भेजे गए, मोहम्मद से वहां बकरियों और ऊंटों की देखभाल कराई गई। मजबूर होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपील की। सऊदी अरब, जो भारत से प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है, विदेशी श्रमिकों के प्रति अपने व्यवहार के लिए बार-बार आलोचनाओं का सामना करता रहा है। मानवाधिकार संगठनों, पत्रकारों और वकालत समूहों की रिपोर्टों ने श्रम अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन को उजागर किया है, जिसके कारण हजारों भारतीय श्रमिक असुरक्षित और क्रूर परिस्थितियों में फंसे रह जाते हैं। सबसे जघन्य उल्लंघनों में वेतन रोकना शामिल है, जहां नियोक्ता अक्सर भुगतान में देरी करते हैं या भुगतान से इन्कार कर देते हैं जिससे कामगार घोर गरीबी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नियोक्ता कामगारों के पासपोर्ट भी जब्त कर लेते हैं जिससे वे देश छोड़कर न जा सकें या मदद न मांग सकें। कई मजदूर पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना जानलेवा वातावरण में काम करते हैं जिससे गंभीर चोटें लगती हैं, यहां तक ??कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कुछ कामगार, विशेषकर घरेलू कामगार, मारपीट, यौन हिंसा और उत्पीड़न का शिकार होने की शिकायत करते हैं। इसी प्रकार, घरेलू कामगारों, जिनमें से कई भारत की महिलाएं हैं, ने अत्यधिक हिंसा और यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट की है। इनमें से काफी संख्या में महिलाओं को उनके मालिकों द्वारा शारीरिक हमले का सामना करना पड़ता है और कानूनी सुरक्षा या नौकरी छोड़ने की क्षमता के अभाव में वे असहाय और सदमे में रह जाती हैं। खाड़ी देशों में अपने नागरिकों की पीड़ा के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया के लिए भारतीय सरकार की आलोचना की गई है। सऊदी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए राजनयिक प्रयास किए गए हैं लेकिन प्रवर्तन और जवाबदेही की कमी के कारण ये पहलें अक्सर विफल हो जाती हैं। इसके अलावा, भारत में भर्ती एजेंसियां और बिचौलिए श्रमिकों की तस्करी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अक्सर अत्यधिक शुल्क वसूलते हैं और नौकरी चाहने वालों को सऊदी अरब में काम करने की वास्तविकताओं के बारे में गुमराह करते हैं। सऊदी अरब में भारतीय कामगारों की दुर्दशा आधुनिक गुलामी की भयावह मिसाल है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों और मानवाधिकार समझौतों के बावजूद आज भी कायम है। जब तक व्यवस्थागत सुधार लागू नहीं होते, हजारों भारतीय कामगार शोषण के दुष्चक्र में फंसे रहेंगे।

सम्पादकीय...

चिंताजनक है 'डीपफेक पोर्नोग्राफी' का चलन

इस समय पोर्नोग्राफी के जरिए प्रभावशाली व्यक्तियों और महिलाओं को ब्लैकमेल करने की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। यह आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस यानि कृत्रिम बुद्धिमता तकनीक का एक बड़ा दुरुपयोग है। यह हमारी सामाजिक चिंताओं में भी वृद्धि कर रहा है। डीपफेक पोर्नोग्राफी के इस्तेमाल के जरिए बिना सहमति वाले व्यक्तियों के अश्लील वीडियो बनाना और सांझे करना शामिल है और इसका इस्तेमाल व्यक्ति की छवि को खराब करने के लिए किया जाता है। डीपफेक पोर्नोग्राफी, या सरल शब्दों में कहें तो एक प्रकार की कृत्रिम पोर्नोग्राफी है, जिसे पहले से मौजूद तस्वीरों या वीडियो में डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस के जरिए आजकल डीपफेक पोर्न बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी अश्लील वीडियो या चित्र जो हमारा नहीं है मगर उस पर हमारा चेहरा लगा दिया जाता है और ये सब इतना सटीक होता है कि सामान्य इंसान इसे पहचान भी नहीं पाता कि यह नकली है या असली। 'डीपफेक' शब्द 'डीप लर्निंग' और 'फेक' का मिश्रण है। इससे वे सब बनाया जा सकता है, जिसे अब 'सिंथैटिक मीडिया' कहा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति के भाव/कार्यों की नकली तस्वीर या वीडियो क्लिप बनाया जा सकता है। यह न केवल दुनिया को मूर्ख बना सकता है, बल्कि आपकी समझ से भी खिलवाड़ कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस के चलते, हर गुजरते दिन के साथ ऐसी डीपफेक तकनीक आसान, सस्ती और अधिक सुलभ होती जा रही है। कम्प्यूटर की सहायता से बनाई गई नग्न तस्वीरों और वीडियो को डीप न्यूड कहा जाता है। हो यह रहा है कि साइबर अपराधी कृत्रिम बुद्धिमता सॉफ्टवेयर की मदद से वीडियो, ऑडियो और तस्वीरों पर नग्न सामग्री का लेप कर देते हैं। कृत्रिम बुद्धिमता का इस्तेमाल कर किसी व्यक्ति के बोलने के तरीके, सिर तथा चेहरे की गतिविधियों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शामिल कर देने से यह बताना मुश्किल हो जाता है कि यह वीडियो/तस्वीरें सही हैं या गलत। कम्प्यूटर द्वारा तैयार की गई इन वीडियो/तस्वीरों की सत्यता की जांच गहन विश्लेषण से ही की जा सकती है। साइबर विशेषज्ञ कहते हैं कि डीपफेक वीडियो और फोटो के फेशियल एज, हेयरलाइन्स, आईब्रो, आईग्लास बार्डर देखकर पहचाना जा सकता है। वीडियो प्ले होने पर आंखों और होंठों के मूवमैंट से डीपफेक वीडियो को पहचाना जा सकता है। इस तरीके से बनाए गए वीडियो और फोटो में हाथों और पैरों की लम्बाई एक समान नहीं होती। इस तरह ऐसे वीडियो को पहचाना जा सकता है। डीपफेक को लेकर आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस और साइबर दुनिया के दुरुपयोग पर नियंत्रण अत्यंत जरूरी है। साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा ऐसा है, जिसकी ओर अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए गलत सामग्री सांझी करने से लोगों के निजता के अधिकार का हनन होता है, ऐसे में इसके खिलाफ कड़ा नियमन करने की आवश्यकता है।

बांग्लादेश में बीएनपी की भारी जीत से भारत के लिए सियासी निहितार्थ

बांग्लादेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने फरवरी 2026 के संसदीय चुनावों में भारी जीत हासिल की है। उसने 300 सीटों में से 151 से 209 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। इससे बंग्लादेश में बीएनपी की भारी जीत से भारत के लिए सियासी निहितार्थ स्पष्ट हैं, क्योंकि यह अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग के पतन के बाद पहला बड़ा चुनाव है, जो 2024 के छात्र-आंदोलन से उभरा था। चूंकि बीएनपी पहले से सत्ता में रहती आई है, इसलिए उसकी जीत के वैश्विक मायने भी हैं। वह यह कि पार्टी कमोबेश पूर्व प्रधानमंत्री स्व.बेगम खालिदा जिया के अधूरे सपनों को ही साकार करेगी। वो भी तब जब उनके पुत्र तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। देखा जाए तो बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी को काफी पीछे छोड़ते हुए प्रचंड जीत दर्ज की है, जहां जमात को महज 42-68 सीटें ही मिली हैं। इसप्रकार तारिक रहमान, जो कि बीएनपी के प्रमुख नेता हैं, देश के संभावित प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बीएनपी की जीत की वजह यह है कि पार्टी ने गरीबी उन्मूलन, भ्रष्टाचार विरोध और विदेशी निवेश पर जोर दिया है। इससे भारत के लिए सियासी मायने भी साफ हैं। भले ही भारत-बीएनपी संबंध ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर पाकिस्तान और जमात से बीएनपी के पुराने गठजोड़ के कारण। इसलिए उनकी जीत से भारत को सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता और चरमपंथी समूहों की चिंता बढ़ सकती है, हालांकि बीएनपी समानता-आधारित संबंधों का वादा कर रही है। खासकर हसीना युग के बाद विदेश नीति में बदलाव से व्यापार, जल बंटवारा और कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। वहीं बीएनपी की जीत से दुनिया के लिए भी सियासी मायने साफ हैं। बीएनपी की जीत बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता ला सकती है, लेकिन विदेश नीति में संतुलन अपनाने से चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं। वहीं दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक बदलाव संभव है, जहां भारत के प्रभाव में कमी और चीन के निवेश (2.1 बिलियन) बढ़ सकता है। वैश्विक रूप से, यह क्षेत्रीय गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है, खासकर म्यांमार शरणार्थी और आर्थिक सुधारों के संदर्भ में। यह ठीक है कि भारत और बीएनपी के बीच संबंध सुधारने के प्रयास चुनाव से पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिसमें एस जयशंकर की तारिक रहमान से बहुत मैत्रीपूर्ण चर्चा शामिल है। हालांकि हसीना के भारत में रहने से तनाव बरकरार है, फिर भी दोनों पक्ष सहयोग बढ़ाने को इच्छुक दिख रहे हैं। इसलिए संभावित सुधार के कदम उठाये जा सकते हैं। खासकर राजनयिक संपर्क बढ़ाना, क्योंकि भारत ने बीएनपी नेताओं से मुलाकातें कीं, जैसे प्रणय वर्मा की मीरजा फखरुल से, जहां बीएनपी ने भारत की सुरक्षा हितों का सम्मान करने का आश्वासन दिया। वहीं, व्यापार और वीजा बहाली के दृष्टिगत यात्रा, व्यापार और वीजा प्रतिबंध हटाने पर फोकस किया जा सकता है, जो हसीना के बाद बाधित हो गए थे। खासकर जल बंटवारा और सीमा मुद्दे हल करना यानी बीएनपी पानी बंटवारे और सीमा हत्याओं (जैसे फेलानी घटना) पर जोर दे रही है। इसलिए कुछ चुनौतियां भी आएंगी, क्योंकि बीएनपी हसीना की प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, जिसे भारत शरण दे रहा है, इससे जन-भावना भी प्रभावित हो रही है। वहीं, जमात-ए-इस्लामी का प्रभाव और पाक-चीन झुकाव भारत की चिंता बढ़ा सकता है। फिर भी भविष्य की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। चूंकि बीएनपी समानता-आधारित पड़ोसी संबंधों का वादा कर रही है, जबकि भारत अल्पसंख्यक सुरक्षा और चरमपंथ विरोध की शर्त रख रहा है। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार, व्यावहारिक आवश्यकताएं रीसेट सुनिश्चित करेंगी, लेकिन ऐतिहासिक अविश्वास दूर करने में समय लगेगा। यद्यपि तारिक रहमान, जो बीएनपी के प्रमुख नेता हैं, और भारत के प्रति संयमित और तटस्थ रुख अपनाते दिख रहे हैं, जो अतीत के तनावपूर्ण रिश्तों से अलग है। वे समानता-आधारित पड़ोसी संबंधों पर जोर देते हैं, लेकिन शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखते हैं। उनका मुख्य स्टैंडपॉइंट्स यह है कि अल्पसंख्यक सुरक्षा और स्थिरता के नजरिए से वो अपने भाषणों में अहिंसा, कानून के राज और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया, जो भारत की चिंताओं को संबोधित करता है। वहीं, समानता का जोर के मद्देनजर बराबरी के रिश्ते चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पुरानी असमानताओं (जैसे जल बंटवारा, सीमा हत्याएं) पर बात उठाई, लेकिन टकराव से बचते हैं। हां, भारत में शरण लेने वाली हसीना को वापस लाने की मांग, जो सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा है। हालांकि हालिया संकेत यही है कि ढाका लौटने के बाद उनके संयमित भाषण को खुफिया एजेंसियां इंडिया-न्यूट्रल मान रही हैं, जो 2001-06 के भारत-विरोधी दौर से अलग है। लिहाजा भारत के साथ सहयोग संभव, लेकिन पाकिस्तान-चीन झुकाव और जमात प्रभाव चिंता का विषय है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि व्यावहारिकता से रिश्ते सुधर सकते हैं। देखा जाए तो तारिक रहमान के हालिया भाषणों में भारत का सीधा जिक्र बहुत कम या न के बराबर आया है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। वहीं उनके भाषणों की मुख्य शैली में भारत का प्रत्यक्ष उल्लेख न करना समाहित है। खासकर ढाका लौटने (25 दिसंबर 2025) के 17 मिनट के पहले भाषण में भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्पसंख्यक सुरक्षा (हिंदू, बौद्ध आदि), अहिंसा और कानून के राज पर जोर दिया–जो भारत की प्रमुख चिंताओं को संबोधित करता है। वहीं, बांग्लादेश फर्स्ट नारा यानी ना दिल्ली, ना रावलपिंडी, सबसे पहले बांग्लादेश कहकर तटस्थ विदेश नीति का संकेत दिया, जो पुराने भारत-विरोधी रुख से अलग है। उनके सकारात्मक संदेश साफ हैं। वो ये कि अंग्रेजी में अंतरराष्ट्रीय अपील की, समावेशी बांग्लादेश का खाका पेश किया, जो खुफिया एजेंसियों ने री-अश्योरेंस सिग्नल माना। देखा जाए तो उनके ये भाषण बीएनपी की री-ब्रांडिंग का हिस्सा है, जहां 2001-06 के भारत-विरोधी दौर से दूरी दिखाई गई। कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह भारत के साथ संबंध सुधारने का रणनीतिक संकेत है, हालांकि हसीना प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे लंबित हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घारती ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साय पैकतमेला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/0882)

महाबोधि महाविहार अधिनियम 1949 के खिलाफ तेज हुआ आंदोलन, बौद्ध समाज ने उठाई प्रबंधन अधिकार की मांग

नई दिल्ली।(विजय कुमार भारती) संपूर्ण विश्व के बौद्धों की सर्वोच्च आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार आज भी बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 की विसंगतियों से जूझ रहा है। बौद्ध समाज का कहना है कि उनके सबसे पवित्र तीर्थ स्थल का प्रबंधन अब तक पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथों में नहीं होना, एक ऐतिहासिक और संवैधानिक अन्याय है। बौद्ध संगठनों का तर्क है कि भारतीय संविधान प्रत्येक धर्म को अपने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार देता है, ऐसे में केवल बौद्धों को इस अधिकार से वंचित रखना लोकतंत्र और समानता की भावना के खिलाफ है। उनका कहना है कि महाबोधि महाविहार केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म की आत्मा और पहचान का प्रतीक है। देशभर में इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन, सभाएं और जनजागरूकता अभियान तेज हो गए हैं। आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि यह संघर्ष अब केवल धार्मिक यह सामाजिक न्याय और

मांग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। बौद्ध समाज के नेताओं का दावा है कि देशभर में फैला बौद्ध समुदाय आज एक संगठित और प्रभावशाली मतदान शक्ति के रूप में उभर चुका है, जो चुनावी राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उनका स्पष्ट संदेश है कि यदि सरकार और प्रशासन ने इस मांग को अनदेखी जारी रखी, तो इसका असर आने वाले चुनावों में दिखाई देगा। आंदोलनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को तत्काल रद्द कर महाबोधि महाविहार का संपूर्ण प्रबंधन बौद्ध समाज को सौंपा जाए। उनका कहना है कि करोड़ों बौद्धों की भावनाओं और अधिकारों की उपेक्षा अब और नहीं की जा सकती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह आंदोलन इसी तरह व्यापक होता गया, तो यह भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

पूर्व आर्मी चीफ की पुस्तक पर संसद में हंगामा !

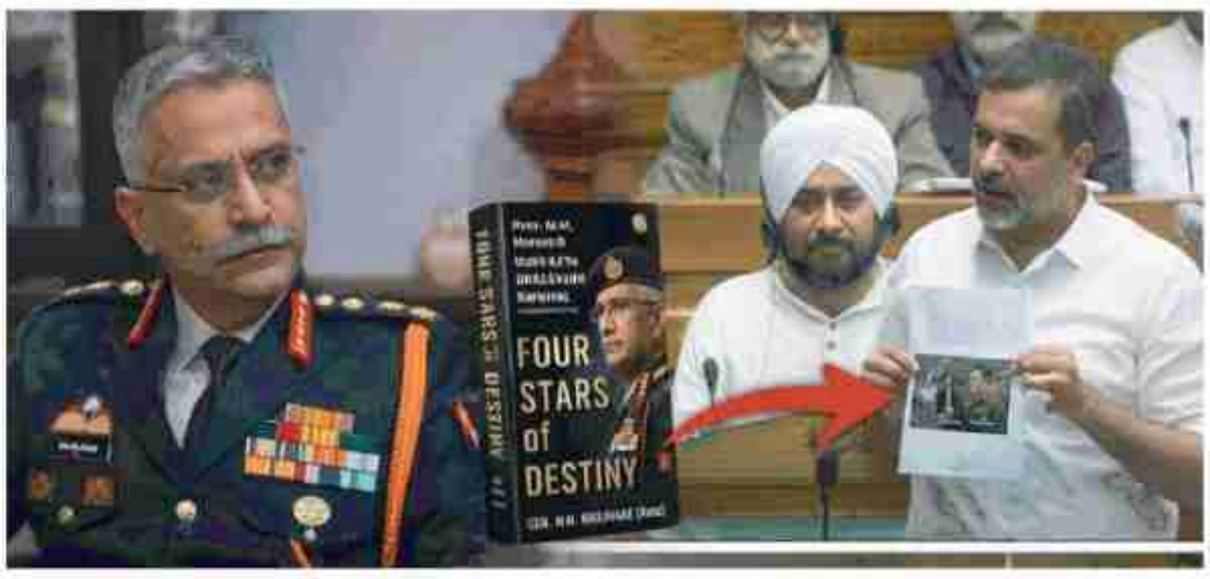

चीन मुद्दे पर गरमाई सियासत पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल, नरवणे की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक Four Stars of Destiny को लेकर संसद के बजट सत्र में तीखा हंगामा देखने को मिला। पुस्तक में चीन के साथ सीमा विवाद और पूर्वी लद्दाख में वर्ष 2020 के घटनाक्रम से जुड़े उल्लेखों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया। सदन में चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि पुस्तक में चीन के साथ सैन्य तनाव, रणनीतिक निर्णयों और राजनीतिक-सैन्य समन्वय से संबंधित संवेदनशील बिंदुओं का उल्लेख है, जिन पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर पारदर्शिता आवश्यक है और यदि पुस्तक में वर्णित तथ्य गंभीर हैं तो उन पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुस्तक के अंशों को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया जा रहा है और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करना उचित नहीं है। हंगामे के कारण कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। हालांकि बाद में पीठासीन अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद कार्यवाही पुनः शुरू की गई। राजनीतिक हलकों में इस पुस्तक को लेकर बहस तेज हो गई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है।

22 फरवरी नागपुर में और 22 फरवरी को बुद्धगया बोधगया में महाबोधि महासंग्राम

महाराष्ट्र (अशोका एक्सप्रेस)बामनों के असंवैधानिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऋस्स प्रमुखों के देखरेख में सरकार शासन प्रशासन के द्वारा 22 फरवरी को बुद्धगया में भी भंते लामा और भतपेलुआ टाइप के लोगों का जमावड़ा किया जा रहा है।

महाबोधि सोसायटी ऑफ इंडिया, बोधगया के जगन्नाथ मंदिर, बोधगया मठ के महंत , अखिल भारतीय भिक्खु संघ बुद्धगया के भंते नहीं चाहते कि विश्व विरासत महाबोधि महाविहार बुद्धगया का नियंत्रण (व्यवस्थापन प्रबंधन) बौद्धों के हाथों में हो। ऊपर लिखित संस्थाओं का संचालन मनुवादियों के शंकराचार्यों द्वारा किया जाता है।

अखिल भारतीय बौद्ध मंच आल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म और सभी बौद्ध संगठनों के समन्वय से संचालित अनिश्चितकालीन धरना को हटाने और समाप्त करने को लेकर माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 से रोज नये नये षड्यंत्र किए गए और मनुवादियों के संगठनों द्वारा संचालित सामनेर भंते द्वारा जनता को भ्रमित करने की साजिश दिल्ली में 12 फरवरी को राजनीतिक लोगों का जमावड़ा किया जा रहा है।

बामनों के असंवैधानिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऋस्स प्रमुखों के देखरेख में सरकार शासन प्रशासन के द्वारा 22 फरवरी को बुद्धगया में भी भंते लामा और भतपेलुआ टाइप के लोगों का जमावड़ा किया जा रहा है।

वर्तमान सरकार के शासन प्रशासन में बैठे

हुए लोगों द्वारा महाबोधि महाविहार की मनुवादी पाखंडियों से मुक्ति के लिए बुद्धगया में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी से माघ पूर्णिमा 01 फरवरी 2026 रविवार को एक साल पूरा हो गया है।

अनिश्चितकालीन धरना का संचालन और व्यवस्थापन आल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म और सभी बौद्ध संगठनों के समन्वय से महासचिव सिरीमान आकाश लामा जी और भंते गणों द्वारा संचालित हो रहा है। इसको बुद्धगया से हटाने के लिए मनुवादियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है।

2रे बुद्धिस्ट ग्लोबल मीट, नई दिल्ली में शामिल एक भंते ने बताया है कि सरकार बौद्धों के लिए क्या क्या नहीं कर रही है?

हरियाणा-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी बैठक - सूरजकुंड से भारत-अफ्रीका सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत

चंडीगढ़ ।

हरियाणा में औद्योगीकरण और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में हरियाणा-अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उद्योग, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में हरियाणा और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापक संभावनाओं पर मंथन किया गया। बैठक में 21 अफ्रीकी देशों के राजदूतों और हाई कमिश्नरों सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधियों तथा नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि सूरजकुंड की पावन एवं सांस्कृतिक धरती से भारत- अफ्रीका साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला लोक परंपरा, हस्तशिल्प, रचनात्मकता और मानवीय कौशल का वैश्विक मंच है, जो सांस्कृतिक जुड़ाव और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत-अफ्रीका संबंध समानता, पारस्परिक सम्मान और साझा

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित पंचजन्य 2026, हरियाणा-अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीट के दौरान 18 देशों के राजदूतों के साथ समूह चित्र में। साथ में हैं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह व अन्य गणमान्य। (13.02.2026)

विकास के सिद्धांत पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हरियाणा राज्य स्तर पर भी अफ्रीकी देशों के साथ दीर्घकालिक और मजबूत संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अलग से विदेश सहयोग विभाग स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य कृषि, विनिर्माण, एमएसएमई, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और स्टार्टअप के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ विकास इंजन है। एनसीआर से जुड़ाव के कारण राज्य को वैश्विक कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक मजबूती प्राप्त है, जिससे अफ्रीकी देशों के साथ बहु-क्षेत्रीय सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। कृषि को भारत-अफ्रीका सहयोग का प्रमुख क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि सिंचाई प्रबंधन, उन्नत बीज, फसल विविधीकरण, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी और पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन में हरियाणा का अनुभव अफ्रीकी देशों की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है। उन्होंने केन्या, तंजानिया, युगांडा, इथियोपिया और रवांडा के साथ संयुक्त खेती, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी साझेदारी की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। तंजानिया निवेश केंद्र तथा कृषि एवं अन्य संस्थानों के साथ हुए समझौतों से व्यापार, निवेश और कृषि सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, आईटी, निर्माण, कौशल विकास, स्टार्टअप, फिनटेक और एमएसएमई क्षेत्रों में भी व्यापक सहयोग की संभावनाएं हैं। दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक और कृषि आधारित साझेदारी विकसित की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण और हरित विकास को साझा नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि सौर ऊर्जा, जल प्रबंधन और पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में संयुक्त प्रयास आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला केवल व्यापार का मंच नहीं, बल्कि रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। जब शिल्प यात्रा करता है, तो संस्कृतियां संवाद करती हैं और साझेदारियां जन्म लेती हैं।

लोकसभा स्पीकर पर आरोप, नरवणे की किताब पर हंगामा... बजट सत्र का पहला हिस्सा इन वजहों से किया जाएगा याद

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज आखिरी दिन है, बजट सत्र का दूसरा भाग अब 9 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक होगा.इस सत्र को कई मायनों में याद किया जाएगा. ये सत्र इस वजह से भी खास रहा क्योंकि 1999 के बाद पहली बार रविवार के दिन आम बजट पेश किया गया,वहीं नहीं यह सत्र विपक्ष के हंगामे को लेकर भी याद किया जाएगा.खासकर तब जब विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया.भारतीय संसद के इतिहास में यह चौथा मौका होगा है जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है.इससे पहले 1954 में जी वी मावलंकर,1966 में सरदार हुकुम सिंह और 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. मगर कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाया और लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहे.इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष ने 118 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव का भी वहीं हाल होगा जो पिछले प्रस्तावों का हुआ है. मगर इस बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने यह निर्णय लिया है कि जब तक उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं हो जाता वो अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे. यह सत्र इसके लिए भी याद रखा जाएगा. लोकसभा में रविवार को बजट पेश होने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व जनरल नरवणे की एक किताब का जिक्र किया.यह किताब भारत में छपी ही नहीं थी और इस बात पर इतना विवाद बढ़ा कि लोकसभा की कार्यवाही पूरे हफ्ते तक नहीं चल पाई.ये सत्र इसके लिए भी याद किया जाएगा जब प्रधानमंत्री करीब दो दशक बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोल पाए.प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं आए बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को बताया कि महिला सांसदों ने उनका रास्ता रोक रखा था और प्रधानमंत्री की जान को खतरा था.विपक्ष के हंगामे की गाज आठ सांसदों पर भी गिरी और उन्हें पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया.सत्र में लेकर अंतिम दिन तक ये सांसद संसद भवन परिसर में धरना करते नजर आए. इस सत्र में बजट पर चर्चा हुई सभी सदस्य जो राष्ट्रपति के बहस में भाग लिया.इसके बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील की खबर भी आई,सरकार ने इसे फादर ऑफ द डील की संज्ञा दी और वाणिज्य मंत्री ने सदन में बयान भी दिया मगर विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया और कृषि क्षेत्र को विदेशी बाजार के लिए खोलने का आरोप सरकार पर लगाया. बजट सत्र के पहले भाग का अंतिम कुछ दिन याद रखा जाएगा राहुल गांधी के खिलाफ कई तरह के प्रस्ताव लाने की कोशिश.सबसे पहले कहा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा मगर ऐन मौके पर सरकार ने इससे मना कर दिया. हालांकि इसी तरह के प्रस्ताव के बाद 1978 में इंदिरा गांधी की सदस्यता जा चुकी है.फिर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ ठोस प्रस्ताव लाने की कोशिश की मगर उसे सदन में अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है.

यूपीए पर बरसे पीएम - पंगु नीति, घोटाले और दिखावे वाले फैसलों का लगाया आरोप

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पिछली कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपीए के समय देश में नीतिगत लकवा, घोटाले और मजबूरी में किए गए सुधार देखने को मिले, जबकि मौजूदा सरकार ने विश्वास और स्पष्ट सोच के साथ काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले देश में हर तरफ घोटालों की चर्चा थी और फैसले लेने में देरी होती थी। इससे दुनिया में भारत की छवि कमजोर हुई। उन्होंने कहा, जब देश में नीतिगत लकवा था और हर तरफ घोटाले थे, तब कौन भारत पर भरोसा करता?% प्रधानमंत्री ने आगे कहा, उस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर था, बड़े देशों के साथ सिर्फ चार ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) थे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में लालफीताशाही ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि पहले सुधार तब होते थे जब देश किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाता था।

पीएम ने 1991 और 26/11 का दिया उदाहरण

प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि साल 1991 में आर्थिक संकट के कारण उदारीकरण करना पड़ा, जब देश लगभग दिवालिया होने की स्थिति में था। इसी तरह 26/11 मुंबई हमले के बाद ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) बनाई गई। उन्होंने कहा कि उस समय फैसले दूरदर्शिता से नहीं, बल्कि मजबूरी में लिए गए।

सरकार की गिनाईं उपलब्धियां

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बजट में पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया है, बायोफार्मा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सेमीकंडक्टर पर खास जोर है। इसके साथ ही भारत अब कई देशों के साथ बड़े व्यापार समझौते कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया भारत पर भरोसा करती है क्योंकि देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है।

भारत का अपना विकास मॉडल- प्रधानमंत्री

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब किसी दूसरे देश का मॉडल कॉपी नहीं करता। साल 2015 में नीति आयोग की स्थापना के बाद से देश ने अपना रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि बदलती दुनिया में हर देश अपनी मजबूती बढ़ा रहा है और भारत वैश्विक विकास का नया इंजन बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दस वर्षों में युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण इलाकों को सशक्त बनाने पर काम हुआ है। नवाचार और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि देश अब संकटों से घिरा हुआ नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ है और दुनिया की प्रगति में बड़ी भूमिका निभा रहा है।

बांग्लादेश की सत्ता में दो दशक बाद बीएनपी की वापसी, पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी जीत की बधाई

नई दिल्ली। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है. अब तक के रुझानों में बीएनपी ने बहुमत हासिल कर लिया है. इसके साथ ही खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना भी लगभग तय हो गया है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को इस जीत के लिए बधाई दी है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बताया कि उन्होंने तारिक रहमान से बात कर उन्हें जीत की बधाई दी है. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, तारिक रहमान से बात करके बहुत खुशी हुई. मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी. मैंने बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उनकी कोशिश के लिए अपनी शुभकामनाएं और समर्थन दिया. पीएम मोदी ने आगे लिखा, दो करीबी पड़ोसियों के तौर पर, जिनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं, मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए, भारत के लगातार कमिटमेंट को पक्का किया. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तारिक रहमान को जीत की बधाई दी. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, शुभेच्छा. बांग्लादेश में मेरे सभी भाइयों और बहनों, सभी लोगों को मेरी हार्दिक बधाई. सभी को रमजान मुबारक. इस बड़ी जीत के लिए तारिक भाई और उनकी पार्टी को मेरी बधाई. दुआ है, आप सभी अच्छे और खुश रहें. ममता बनर्जी ने उम्मीद जताई कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अच्छे बने रहेंगे.

पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ का किया उद्घाटन

"नए पीएमओ सेवा तीर्थ से पीएम मोदी का पहला एक्शन, महिलाएं-किसान बने प्राथमिकता

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महिलाओं, युवाओं और कमजोर नागरिकों से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर किए। यह उनके द्वारा लुटियंस दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित ब्रिटिश-युग के कार्यालय से अपने नए कार्यालय सेवा तीर्थ में स्थानांतरित होने के बाद लिए गए निर्णयों का पहला चरण था। प्रधानमंत्री ने अपने नए कार्यालय से लिए गए पहले निर्णयों में राहत योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी, लखपति दीदियों के लक्ष्य को दोगुना कर दिया और कृषि अवसंरचना कोष के आवंटन में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों का एक नया और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पैमाने और आकांक्षा दोनों को दोगुना कर देता है। यह लक्ष्य मूल मार्च 2027 की समयसीमा से एक वर्ष से भी अधिक पहले, 3 करोड़ लखपति दीदियों के निर्माण के बाद प्राप्त हुआ है।

भारत की संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष के आवंटन को 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का अनावरण किया। गौरतलब है कि यह उद्घाटन भारत की प्रशासनिक शासन संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दशकों से, कई प्रमुख सरकारी कार्यालय और मंत्रालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में कई स्थानों पर फैले हुए खंडित और पुराने ढांचे से काम कर रहे थे। इस फैलाव के कारण परिचालन में अक्षमताएँ, समन्वय संबंधी चुनौतियाँ, रखरखाव की बढ़ती लागत और काम करने के लिए अनुपयुक्त वातावरण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि नए भवन परिसर आधुनिक, भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं के भीतर प्रशासनिक कार्यों को समेकित करके इन समस्याओं का समाधान करते हैं। सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं, जो पहले अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में कानून, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि और कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय स्थित हैं।

राहुल गांधी की ट्रेड डील के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी? किसान संघ के नेताओं से की मुलाकात

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया व्यापार समझौते पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है।

वो लगातार आरोप लगा रहे है कि ट्रेड डील किसानों की रोजी-रोटी छीनेगा और देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करने वाला है। राहुल गांधी ने लोकसभा में व्यापार समझौते को किसान विरोधी बताया है। इस कड़ी में अब शुक्रवार (13 फरवरी) राहुल गांधी ने किसान संघों के नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में देश भर के किसान संघों के नेताओं से मुलाकात की, जिसमें भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का विरोध करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की आवश्यकता के साथ-साथ किसानों और कृषि मजदूरों की आजीविका की रक्षा करने पर चर्चा की गई। कांग्रेस ने बताया कि बैठक के दौरान किसान संघ के नेताओं ने अपना विरोध जताया और मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की आजीविका के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। पार्टी ने कहा गया है कि किसान नेताओं और राहुल गांधी ने इस समझौते का विरोध करने और किसानों-कृषि मजदूरों की आजीविका की रक्षा करने के लिए एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत पर चर्चा की। बता दें कि राहुल गांधी से मिलने वाले किसान नेताओं में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रमुख सुखपाल एस खैरा, भारतीय किसान मजदूर यूनियन, हरियाणा के अशोक बल्हारा, बीकेयू क्रांतिकारी के बलदेव एस जीरा, प्रगतिशील किसान मोर्चा के आर नंदकुमार, बीकेयू शहीद भगत सिंह के अमरजीत एस मोहरी, किसान मजदूर मोर्चा - भारत के गुरमनीत एस मंगत और जेके जमींदारा फोरम के हमीद मलिक शामिल थे। यह बैठक राहुल गांधी के उस बयान के एक दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार उनके खिलाफ मामले या विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन वे किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसान विरोधी होने और भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के जरिए देश को बेचने का भी आरोप लगाया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक्स पर एक वीडियो बयान साझा किया था, जिसमें उन्होंने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया था। एक्स पर वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएं - मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी-रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान-विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान-विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे।

राहुल के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाएगी सरकार, भाजपा सांसद ने दिया है नोटिस- किरेन रीजीजू

नई दिल्ली।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की योजना छोड़ दी है क्योंकि भाजपा के एक सांसद ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता के खिलाफ एक विशिष्ट प्रस्ताव शुरू करने के लिए नोटिस दिया है। रीजीजू ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष से सलाह ली जाएगी कि इस मामले को सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए, आचार समिति को भेजा जाए या सीधे लोकसभा में लाया जाए। उन्होंने कहा, अभी यह तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चूंकि एक सदस्य ने निजी तौर पर प्रस्ताव के लिए पहले ही नोटिस दे दिया है, इसलिए सरकार अपना प्रस्ताव पेश करने से बचेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को पीटीआई-वीडियो से कहा था कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशिष्ट प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस दिया है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सदन की सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। दुबे के अनुसार, उन्होंने अपने नोटिस में कहा है कि कैसे नेता प्रतिपक्ष विदेश जाते हैं और भारत विरोधी तत्वों के साथ सांठगांठ करते हैं। विशिष्ट प्रस्ताव स्वतंत्र होता है, जिसे सदन की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और जिसे किसी फैसले या राय को व्यक्त करने के लिए तैयार किया जाता है। दुबे ने कहा, कोई विशेषाधिकार हनन नोटिस नहीं दिया है। मैंने एक विशिष्ट प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है।

बेंगलुरु के पास आपस में टकराए कई वाहन, 7 लोगों की दर्दनाक मौत

बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में शुक्रवार की सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। होसकोटे के बाहरी इलाके में कई वाहनों की आपस में भिड़ंत होने से कम से कम सात लोगों की जान चली गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह दुर्घटना होसकोटे -डबासपेट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एम. सत्यवारा गांव के पास हुई। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले के होसकोटे के बाहरी इलाके में कई गाड़ियों के टकराने से कम से कम सात लोगों की जान चली गई। यह घटना होसकोटे डबासपेट नेशनल हाईवे पर एम सत्यवारा गांव के पास हुई। इस हादसे में एक मोटरसाइकिल, एक कार और एक कैंटर ट्रक शामिल थे। कर्नाटक पुलिस के मुताबिक, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल होसकोटे से देवनहल्ली जा रही थी। हालांकि, एसयूवी ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और उसने कार के सामने वाली मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इससे अफरा-तफरी मच गई और एक कैंटर ट्रक भी इस हादसे में शामिल हो गया। कर्नाटक पुलिस ने बताया कि इस टक्कर में एसयूवी में सवार छह लोगों की मौत हो गई। मोटरसाइकिल सवार की भी मौत हो गई। हालांकि, मरने वालों की पहचान अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि वे बेंगलुरु के कोथनूर के रहने वाले थे। कर्नाटक पुलिस ने बताया कि उनके शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए होसकोटे सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है, साथ ही एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के हटाया भाषण का हिस्सा- खरगे

नई दिल्ली। राज्यसभा में शुक्रवार (13 फरवरी) को बोलते हुए विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने पिछले संबोधन के बड़े हिस्से को सदन के रिकॉर्ड से हटाने पर नाराजगी जताई। खरगे ने कहा कि 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी औचित्य के आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया था।

खरगे ने इस कदम को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हटाए गए भाषण में सरकार की नीतियों की आलोचनाएं शामिल थीं, जिसे उन्होंने एक विपक्षी सदस्य के रूप में उजागर करना अपना कर्तव्य बताया। इसी के उन्होंने हटाए गए भाषण के हिस्सों को बहाल करने का भी आग्रह किया। राज्यसभा में बोलते हुए खरगे ने कहा, 4 फरवरी, 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। जब मैंने राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया वीडियो देखा, तो मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिना किसी उचित स्पष्टीकरण या औचित्य के हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि समीक्षा करने पर मैंने पाया कि हटाए गए हिस्से में संसद में वर्तमान सरकार के कामकाज पर मेरी टिप्पणियां और तथ्यात्मक संदर्भ शामिल थे। मैंने प्रधानमंत्री की कुछ नीतियों की आलोचना भी की, जो विपक्ष के सदस्य के रूप में मेरा कर्तव्य है, विशेषकर तब जब इन नीतियों का जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता प्रतीत होता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने पांच दशकों से अधिक समय तक सांसद के रूप में सेवा की है, एक विधायक और संसद सदस्य के रूप में समर्पण के साथ काम किया है, हमेशा गरिमा, शिष्टाचार और भाषा के प्रति सम्मान को बनाए रखा है। इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि मेरे भाषण के जिन अंशों को हटाया गया है, उन्हें बहाल किया जाए, क्योंकि उनमें कोई असंसदीय या मानहानिकारक शब्द नहीं है, और न ही वे नियम 261 का उल्लंघन करते हैं। मेरे भाषण के इतने बड़े हिस्से को हटाना लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। जिस पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने खरगे के हटाए गए बयानों को बहाल करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हटाए गए अंशों को बहाल नहीं किया जा सकता और इस बात पर जोर दिया कि इस मामले पर अध्यक्ष को निर्देश देना सही नहीं और लोकतांत्रिक नहीं है।

लखनऊ, अयोध्या व काशी समेत 19 कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट जारी कर खाली कराया गया परिसर

अयोध्या। यूपी में लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी समेत 19 जिलों की कचहरी में बम विस्फोट करने की धमकी भरे मेल से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही कचहरी परिसर को तत्काल खाली करा लिया गया है। इस घटना के मद्देनजर पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कचहरी को वकीलों व वादकारियों से खाली कराया जा रहा है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंच गई है और परिसर की गहन तलाशी ली जा रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। धमकी भरे मेल की जांच की जा रही है कि यह किसने और क्यों भेजा है। सीजेएम ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली है। सीओ सिटी सहित काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। सूत्रों का कहना है कि धमकी भरा मेल जिला जज की मेल आईडी पर आया था। हिंदी में लिखे गए मेल में कहा गया था कि आज दोपहर डेढ़ बजे जुम्मे के बाद कचहरी को बम से उड़ा दिया जाएगा। बच सको तो बच लो। लखनऊ के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने के बाद कोर्ट परिसर में जांच और सुरक्षा एजेंसीयां पहुंची है।

स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर अफसर मौजूद हैं। एलआईयू, बीडीडीएस और डॉग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट के सभी एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर सुरक्षाकर्मी सतर्क हो गए हैं। फिलहाल कोर्ट का कामकाज रोक दिया गया है और कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट में ढूंढने के लिए फोर्स सर्च ऑपरेशन चला रही है।

हंगामेदार रहा बजट सत्र का पहला चरण, 9 मार्च तक कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली।

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के संस्मरण से जुड़े विवाद को लेकर कई दिनों तक चले तीखे राजनीतिक वाद-विवाद के बाद शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया। यह विवाद संसद के बाहर भी चर्चा का विषय बना रहा। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका दोनों सदन अब तीन सप्ताह के अवकाश पर चले गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 9 मार्च को फिर से शुरू होगी। बजट सत्र, जो 28 जनवरी को राष्ट्रपति के संसद को दिए गए संयुक्त संबोधन के साथ शुरू हुआ था, 65 दिनों में 30 बैठकों के साथ समाप्त होगा। मध्यावधि अवकाश के दौरान स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान अनुरोधों की जांच करेंगी। लोकसभा में दो फरवरी से राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव और इसका समर्थन करने के लिए भाजपा के दो सदस्यों के भाषण के बाद जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखनी शुरू की तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण चर्चा नहीं हुई और न ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस पर जवाब हो सका। हालांकि लोकसभा में इस सप्ताह आम बजट पर चर्चा हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को इसका जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति नहीं देने और आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के मामले में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा महासचिव को एक नोटिस दिया है। सूत्रों ने कहा कि नोटिस बजट सत्र के द्वितीय चरण की शुरुआत होने पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। उच्च सदन में भी 2 फरवरी से राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच फरवरी को जवाब दिया था। राज्यसभा में नौ मार्च से आम बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू हुई थी जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 फरवरी को दिया। कल ही उच्च सदन में औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया गया था।

आज की कार्यवाही

आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा में सरकार से मांग की कि थल सेना में भर्ती के लिए परीक्षा पास कर चुके युवाओं की तत्काल भर्ती की जाए और सैनिकों को वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा में लगाना बंद किया जाए। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए सिंह ने कहा कि 2019 से 2022 के बीच लगभग 1.23 लाख युवाओं ने थल सेना में भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा पास की, जबकि लगभग 7,000 उम्मीदवारों ने वायुसेना के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से कोडीन आधारित कफ सिरप के सेवन से जुड़ी मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। नड्डा ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही। राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य सज्जाद अहमद किचलू ने शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर के छात्रों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान के एक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश देने की प्रतिबद्धता पूरी न किए जाने के कारण इन छात्रों का भविष्य अधर में है। किचलू ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि जम्मू के कई छात्रों ने राजस्थान स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए आवेदन किया लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें प्रवेश दिलाने का आश्वासन दिया था।